ख. अपर सचिव (उपभोक्ता मामले) के पीपीएस
ग. सलाहकार (लागत) के पीपीएस
घ. सभी स्कीमों के विभाग प्रमुख

अनुलग्नक

1. उपभोक्ता संरक्षण(विज्ञापन और प्रचार) (सीएस) -

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2026-27
18.00	1. विभिन्न माध्यमों से उपभोक्ता जागरूकता	1.1 मेलों आदि में सहभागिता के माध्यम से जागरूक किए गए लोगों की संख्या	10,00,000	1. उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि	1.1 पिछले वर्ष की तुलना में कुल उपभोक्ता शिकायतों में प्रतिशत वृद्धि (जिसमें विभाग के उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर	10
		1.2 डिजिटल अभियानों की संख्या	04			

		1.3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उपभोक्ता मामलों पर जागरूकता प्रसार हेतु तैयार किए गए ऑडियो-विजुअल विज्ञापनों की संख्या	60		प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं)	
		1. 4 ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उपभोक्ता मामलों से संबंधित पोस्टों की संख्या	1,500			

2. उपभोक्ता संरक्षण – एकीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली (आईसीजीआरएस) (सीएस)

आउटपुट 2026-27				आउटकम 2026-27		
वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट	संकेतक	प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य	आउटपुट	संकेतक	प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य
8.74 (प्रस्तावित बजट अनुमान के अनुसार)	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन द्वारा शिकायतों का निपटान	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की संख्या	14,00,000	उपभोक्ता शिकायतों का निपटान	पिछले वर्ष की तुलना में निपटाई गई शिकायतों की औसत संख्या में प्रतिशत परिवर्तन	17%

3. स्कीम: उपभोक्ता संरक्षण: उपभोक्ता आयोग का सशक्तिकरण (एससीसी)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ ₹ में)	ऑउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
	ऑउटपुट	संकेतक(ओं)	प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य	परिणाम संकेतक	संकेतकों	प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य
अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	उपभोक्ता आयोगों का आधुनिकीकरण	देश में स्थित राज्य और जिला आयोगों में प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों की संख्या।	1,30,000	उपभोक्ता मामलों का निपटारा और उपभोक्ता आयोगों के कामकाज में सुधार	उपभोक्ता मामलों के निपटान में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत वृद्धि	2%

4. स्कीम: कॉन्फोनेट

वित्तीय परिव्यय (करोड़ ₹ में)	ऑउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
	ऑउटपुट	संकेतक(ओं)	लक्ष्य 2025-26	परिणाम संकेतक	संकेतकों	लक्ष्य 2025-26
अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	केस मॉनिटरिंग/निर्णय आदि के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।	1.दर्ज मामलों की संख्या	1,40,000	रिपोर्टिंग और निगरानी तथा पहुंच को सुविधाजनक बनाना।–	पिछले वर्ष की तुलना में उपभोक्ता मामलों में प्रतिशत वृद्धि	3%
		2. निपटान दर	5%			

5. विधिक मापविज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन: भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/परख केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो स्कीम (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ ₹ में)	ऑउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	ऑउटपुट	संकेतक(ओं)	लक्ष्य 2026-27	परिणाम	संकेतकों	लक्ष्य 2026-27
1.00	परख/हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और मान्यता ए एंड एच केंद्रों के कारीगरों, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, बीआईएस अधिकारियों के लिए	1.1 स्थापित हॉलमार्किंग और परख केंद्रों की संख्या	13	1. कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग के लिए सुविधाओं में वृद्धि	1.1. स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग के लिए सुविधाओं की संख्या में प्रतिशत (%) वृद्धि	12
		1.2 कारीगरों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या,	10	2. आवश्यक मानकों के अनुसार गहने बनाने वाले कारीगरों में सुधार, जिसमें परख और हॉलमार्किंग	2.1 उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगरों की संख्या में प्रतिशत (%) वृद्धि	05
		1.3 ए			2.2	

	ए एंड एच केंद्रों के लेखापरीक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	एंड एच केंद्रों के कारीगरों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	04	शामिल है, और परीक्षण और हॉलमार्किंग के लिए प्रशिक्षित ए एंड एच कर्मी उपलब्ध हैं।	उपलब्ध प्रशिक्षित ए एंड एच कर्मियों की संख्या में प्रतिशत (%) वृद्धि	06
		1.4 ए एंड एच केंद्रों के लेखापरीक्षा के लिए प्रशिक्षित बीआईएस अधिकारियों की संख्या	25	3. ए एंड एच केंद्रों के लिए लेखापरीक्षा करने हेतु बीआईएस अधिकारियों की क्षमताओं में वृद्धि।	3.1 उपलब्ध प्रशिक्षित लेखापरीक्षकों की संख्या में प्रतिशत (%) वृद्धि	08
		1.5 हॉलमार्क किए गए वस्तुओं की संख्या (करोड़ में)	12	4. हॉलमार्क वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि	4.1 हॉलमार्क स्वर्ण आर्टिकल की संख्या में प्रतिशत (%) वृद्धि	12

6. विधिक मापविज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन – राष्ट्रीय परीक्षणशाला (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)	आउटपुट 2026-27			परिणाम 2026-27		
2026-27	आउटपुट	संकेतक	वार्षिक लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	वार्षिक लक्ष्य
	देश भर के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अलग-अलग प्रकार के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों के लिए गुणवत्ता परीक्षण की सुविधा देना।	जोड़े गए या उन्नत किए गए नए परीक्षण सुविधा-केंद्रों की संख्या	4	इंजीनियरिंग विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में इंजीनियरिंग सामग्री और उत्पादों के परीक्षण, अंशांकन और गुणवत्ता मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यापक सेवाएं प्रदान करना। उद्योगों को विशेष रूप से विफलता विश्लेषण, गुणवत्ता संवर्धन तथा परीक्षण अभियांत्रिकी में अनुसंधान एवं	i) जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्रों की संख्या के मामले में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत	30%
	ग्राहक प्रतिधारण, व्यवसाय और भौगोलिक पहुंच विस्तार, परिचालन	i) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निरीक्षण किए गए	30%		ii) कमाए गए राजस्व के मामले में वार्षिक वृद्धि का प्रतिशत	

	दक्षता और लागत नियंत्रण द्वारा वार्षिक राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए राजस्व धाराओं में विविधता लाना।	नमूनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ii) पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में राजस्व वृद्धि		विकास कार्य के साथ-साथ परीक्षण और अंशांकन विधियों के विकास के क्षेत्रों में परामर्श सेवाए प्रदान करना।		

7. विधिक मापविज्ञान और गुणवत्ता आश्वासन: बाट और माप की अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान (सीएस) को सुदृढ़ करना

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	आउटपुट **2026-27**					परिणाम **2026-27**				
2026-	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य **20**	लक्ष्य (संख्या में)	उपलब्धि (संख्या में)	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य **20**	लक्ष्य **2026-27**	उपलब्धि (संख्या में)

27			26-27 वार्षिक	प्रश्न 1	प्रश्न 2	प्रश्न 3	चौथी तिमाही	प्रश्न 1	प्रश्न 2	प्रश्न 3	चौथी तिमाही			26-27 वार्षिक	(संख्या में) प्रश्न 1	प्रश्न 2	प्रश्न 3	चौथी तिमाही	प्रश्न 1	प्रश्न 2	प्रश्न 3	चौथी तिमाही
65	1. बाट और माप की अवसंरचना की स्थापना	1.1 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित नई बाट और माप अवसंरचनाओं की संख्या	20	5	5	5	5					1. बाट और माप के अंशांकन, सत्यापन और मुद्रांकन की सेवाएं प्रदान करना	बाट और माप के अंशांकन/सत्यापन की संख्या में % वृद्धि	5 %								

	2. आरआरएसएल और आईआईएलएम, रांची सहित विभिन्न परीक्षणों के लिए मानक उपकरणों की खरीद	2.1 आरआरएसएल में स्थापित मानक उपकरणों की संख्या	10	2	3	3	2					2. आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	2.1 प्रशिक्षित/प्रमाणित उद्योगों/व्यक्तियों की संख्या में % वृद्धि	5 %							
	3. बाट और माप के उपकरणों का निरीक्षण	3.1 जांचे गए कुल उपकरणों में से मानक के अनुसार पास हुए उपकरण का %	100 %									3. परीक्षण किए गए उपकरणों की संख्या	3.1 कुल आवश्यकताओं में से निरीक्षण किए गए उपकरणों का %	100 %							

8. पीएसएफ: पीएसएफ के तहत बाज़ार हस्तक्षेप के आउटपुट/परिणाम लक्ष्य

	आउटपुट	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31
आउटपुट संकेतक (केपीआई आवश्यकता)	1. दालें: दालों की भारित औसत खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखना। (चना दाल, तूर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मसूर दाल के लिए संयुक्त भारित औसत खुदरा मूल्य की गणना सीपीआई भार	5.42% से 8.39%	5.42% से 8.39%	5.42% से 8.39%	5.42% से 8.39%	5.42% से 8.39%

	का उपयोग करके की जाती है)।					
	2. दालें: राज्यों में दालों की भारित औसत कीमतों के स्थानिक फैलाव को बनाए रखना।	0.222	0.211	0.201	0.190	0.179
	3. दालें: दालों की मंडी कीमतों पर खुदरा बिक्री का औसत मूल्य मार्क-अप बनाए रंखना।	37.15%	36.65%	36.15%	35.65%	35.15%
	4. प्याज: प्याज की औसत खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखना।	7.21% से 46.81%	7.21% से 46.81%	7.21% से 46.81%	7.21% से 46.81%	7.21% से 46.81%
	5. प्याज: राज्यों में प्याज की कीमतों का स्थानिक फैलाव बनाए रखना।	0.479	0.463	0.448	0.432	0.417
	6. प्याज:	48.18%	47.17%	46.17%	45.17%	44.17%

	प्याज की मंडी कीमतों पर खुदरा बिक्री का औसत मूल्य मार्क-अप बनाए रखना।					
	7. मूल्य रिपोर्टिंग केन्द्रों द्वारा दैनिक मूल्य रिपोर्टिंग में नियमितता बनाए रखना	95%	95%	95%	95%	95%
आउटकम संकेतक (केपीआई आवश्यकता)	सीपीआई में दालों और उत्पादों की महंगाई दर बनाए रखना	4% - 6%	4% - 6%	4% - 6%	4% - 6%	4% - 6%
	सीपीआई में प्याज की महंगाई दर बनाए रखना	<16%	<16%	<16%	<16%	<16%